301

संख्याः —/XXXVI(1)/2012–75/2007–टी0सी0

प्रेषक,

जयदेव सिंह,
प्रमुख सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

महाधिवक्ता,
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर,
नैनीताल।

न्याय अनुभागः1

देहरादून : दिनांक 12 फरवरी, 2014

विषय : मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में राज्य की ओर से पैरवी/बहस हेतु श्री विनोद शर्मा को उप महाधिवक्ता के पद पर आबद्ध किया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम राज्यपाल सम्यक विचारोपरान्त मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के समक्ष राज्य की ओर से पैरवी/बहस किये जाने हेतु श्री विनोद शर्मा को उप महाधिवक्ता के पद पर आबद्ध करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उपर्युक्त आबद्धता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि यह एक व्यवसायिक आबन्धन है, किसी 'सिविल पद' पर नियुक्ति नही है। इस आबन्धन को उत्तराखण्ड राज्य द्वारा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के और बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है तथा आबद्ध अधिवक्ता भी इसे कभी भी समाप्त कर सकते है। आप अपनी आबद्धता के दौरान उत्तराखण्ड राज्य के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार के मामले में किसी अन्य व्यक्ति/संस्था की आबद्धता स्वीकार नही करेंगे न ही राज्य के विरूद्ध कोई विधिक परामर्श देंगे। आबद्ध अधिवक्ता विधि परामर्शी निदेशिका के उपबन्धों का कड़ाई से पालन करेंगे।

3– कृपया श्री विनोद शर्मा को तद्नुसार सूचित करने तथा आबन्धन हेतु उनकी सहमति प्राप्त कर उन्हें तद्नुसार कार्य करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा भुगतान महाधिवक्ता को सहमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद देय होगा।

4– श्री विनोद शर्मा को न्याय विभाग के शासनादेश संख्या–67/XXXVI(1)/2010 –43–एक(1)/03 दिनांक 25–03–2010 के अनुसार फीस देय होगी।

5– यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

6– सम्बन्धित अधिवक्ता इस आशय का प्रमाण पत्र भी महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड के माध्यम से शासन को प्रस्तुत करेंगे कि उन्हें इन शर्तों पर कोई आपत्ति नहीं है।

भवदीय,

(जयदेव सिंह)
प्रमुख सचिव

C:\Users\law\Desktop\Dgc apointment\dgc letter.docx

संख्या–१४१९ (1)/XXXVI(1)/2012–75/2007–टी0सी0 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मा0 मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव/सचिव/निजी सचिव।
2– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के स्टाफ आफीसर/निजी सचिव।
3– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
4– महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
5– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6– वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
7– मुख्य स्थायी अधिवक्ता/शासकीय अधिवक्ता, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
8– सम्बन्धित अधिवक्तागण, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।
9– गार्ड फाईल/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

(मनीष मिश्र)
अपर सचिव

C:\Users\law\Desktop\Dgc apointment\dgc letter.docx